उपकर बकाया राशि का भुगतान प्राधिकरण को कब तक किये जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस0 बी0 नयमेगौड़ा) : (क) कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय के रूप में, बिहार कोयला खनन क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 को बनाए जाने के साथ, वर्ष 1986 में बनाई गई थी ।

(ख) टन संबंधी उपकर को लगाए जाने का कार्य दिनांक 1–10–1986 से शुरू हुआ था, और इसे कोयले के खरीददारों से वसूल किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

Import of Coal

3841. SHRI RANJTT SINGH : DR. JINENDRA KUMAR JAIN : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the country has to import coal because of the dearth of good quality coal ;

(b) if so, the average annual import of coal during the past three years together with the cost thereof ;

(c) whether it is also a- fact that there is dearth of washeries in the country, if so' the number of washeries in the public sector, together with their capacity and what percentage of their capacity was utilised during each of the three years;

(d) whether in view of limited capa cities of the washeries. Government pro pose to encourage setting up of wash ;ries in the private sector and the details thereof ; and

(e) If not, what are the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAG0UDA) : (a) Indian coal resources by their very nature are of high ash content and inferior quality. The proportion of good grades of coal resources is only about 25% that too are localised in Bihar-Bengal and Central India Coalfields. While other indus-rial consume have been able to adjust the combustion equipment to suit the indigenously available grades of coal, the steel plants want lower ash content in the coking coal for coke production. It is in this context that steel plants have been importing about 25 x, of their total requirements of coking coal for the purpose of blending-low ash imported coal with high ash indigenous coal.

(b) The present installed capacity of coking coal washeries in the country is more then the present availability of raw coking coal of the type needed for these washeries which were originally desig ned on superioer coking coal, then avail able in the country .

(c) and (d) No proposal has been received for setting up of washeries in private sector for washing of coal produced by.CIL and SCCL.

विभिन्न कोयला एककों द्वारा देश कोयले का उत्पादन

3842. **डा0 जिनेन्द्र कुमार जैन : श्री राम जेठमलानी :**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 में विभिन्न कोयला एककों की कोयला उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी और क्या देश अपनी क्षमता के अनुसार कोयले का उत्पादन कर रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रभावशाली उपाय किये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी0 ए0 संगमा : (क) कोल इंडिया लि0 ग्रुप की खानों की मूल्यांकन खान क्षमता वर्ष 1990–91 में 213.59 मि0 टन और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि0 की खान क्षमता 22.90 मि0 टन थी । इसकी तुलना में वर्ष 1990–91 में कोल इंडिया लि0 में कोयले का उत्पादन 189.66 मि0 टन हुआ जबकि सिंगरेनी कोलियरीज़ कं0 लि0 में 17.71 मि0 टन रहा ।

(ख) मुख्यतः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० से श्रम क्षमता के उपयोग की सूचना मिली है। ई० को० लि० और भा० को० को० लि० में गिरावट का मुख्य कारण बहुत सी कम क्षमता वाली भूमिगत खानों का होना है, जहां उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। उत्पादकता में सुधार लाए जाने के विचार से इन खानों का पुनर्गठन किया जा रहा है। सि० को० कं० लि० में क्षमता उपयोग में कमी होने का मुख्य कारण कोयला क्षेत्रों के आसपास और अन्दर कानून और व्यवस्था की चल रही परिस्थिति के कारण कार्य का ठप्प होना और हड़तालों का होना है। इस मामले की आंध्र प्रदेश सरकार के साथ नियमित रूप में कार्यवाही की जा रही है।

देश के उत्तरी क्षेत्र को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति

3843. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1992 के "दि फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में "नार्दन रोजन हिट बाई इनएडिकवेट कोल, आयरन सप्लाई" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तरी भारत में स्थित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही थी जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में कोयले की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई उपयुक्त कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० नवलेगौड़ा : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अनंतिम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में अप्रैल से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 51.84 मि० टन कोयला प्रेषित किया गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 45.72 मि० टन कोयले का प्रेषण किया गया था। किंतु औद्योगिक उपभोक्ताओं की, जिसमें उत्तर क्षेत्र के कुछ उपभोक्ता भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को, मुख्यतः विद्युत उपयोगिताओं को रेल अथवा सड़क द्वारा कोयले के संचालन में प्राथमिकता दिए जाने के कारण कोयले की कम आपूर्ति का सामना करना पड़ा। कोयला कंपनियों को, सभी उपभोक्ताओं की कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और जहां तक गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं का संबंध है, कोयला कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़क अथवा रेल द्वारा उन्हें संयोजित कोयले की मात्रा में से न्यूनतम 50% मात्रा की आपूर्ति करें।

एस० ई० सी० एल० द्वारा कोयले के उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य

3844. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कितने एकक कोयला उत्पादन में लगे थे तथा क्या इन एककों के लिए कोयला उत्पादन तथा वितरण के भी कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;